There is no way of completely eliminating this situation except by making the cadre of Inspectors an All-India one which, besides being not administratively feasible, would cause hardship to the officers as they would then become liable for transfer all over India.

Deficits Actuals for 1974-75, 1975-76 and 1976-77

3364. SHRI R. VENKATARAMAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the deficit according to the revised estimates for the years 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77;

(b) the actual deficits for the foregoing years; and

(c) the reasons for the variations, if any?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) In the Revised Estimates the deficit was estimated at Rs. 650 crores in 1973-74, Rs. 625 crores in 1974-75, Rs 490 crores in 1975-76 and Rs. 425 crores in 1976-77.

(b) The actual budgetary deficit as shown in the Audit Reports on the accounts for these years was Rs. 328 crores in 1973-74, Rs. 629 crores in 1974-75 and Rs. 399 crores in 1975-76. The Finance Accounts and the Report on the accounts for the year 1976-77 have not yet been received from the Comptroller and Auditor General; according to provisional figures received from the Accountant General, Central Revenues, the deficit for the year amounted to Rs. 154 crores.

(c) The difference between the figures of deficit according to the Revised Estimates and accounts is the net result of variations under several receipt and expenditure heads. Broadly speaking, the variation in 1973-74 was due to larger small savings collections and repayment of advances by foreign Governments, shortfalls in Plan expenditure and defence expenditure. The variation in 1974-75 was negligible. The variations in 1975-76 and 1976-77 are attributable to larger revenue receipts and shortfalls in Plan expenditure. The details of receipts and expenditure for the years 1973-74, 1974-75 and 1975-76 are contained in the Finance Accounts for those years which have been laid on the Table of the Parliament. The provisional figures of receipts and expenditure for the year 1976-77 are shown in the Annual Financial Statement for 1978-79 which has also been laid before the Parliament.

सरकारी उद्योगों में पूंजी निवेश और कार्यरत कर्मचारी

3365. श्री राम किशन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्योगों मे 31 मार्च, 1977 को कुल कितनी राशि का पूंजी निवेश था और उनमें कितने कर्मचारी रोजगार पर थे और क्या राज्यवार पूंजी निवेश और उन में कर्मचारियों की संख्या के बारे में एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) क्या राजस्थान मे सरकारी उद्योगों में पूंजी निवेश अन्य राज्यों की तुलना मे बहुत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये अगले वर्ष राजस्थान मे कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). 31 मार्च, 1977 को केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों मे कुल 11451 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश (सकल परि-

सम्पत्ति) था । इसमें से राजस्थान में पूंजी निवेश 227 करोड़ रुपये का था । राज्यवार पूंजी निवेश के आंकडे संलग्न विवरण I मे दिए गए हैं ।

31-3-1977 को कर्मचारियों की कुल संख्या 14 90 लाख थी । कर्मचारियों का राज्यवार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है तथा इसे सदन पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) राजस्थान के लिए 1978-79 की वार्षिक योजना मे शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित उद्योग (विशाल, मध्यम और खनिज विकास) सम्बन्धी योजनाओ के बारे मे सूचना संलग्न विवरण II मे दी गई है ।

विवरण-I

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3365, जिसका उत्तर 17 मार्च, 1978 को दिया जाना है, मे सम्बन्धित अनुबन्ध ।

राज्य का नाम	पूंजी निवेश (करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	390 7
असम	312 9
बिहार	2509 1
दिल्ली	400 7
गुजरात	523 4
हरियाणा	142 7
हिमाचल प्रदेश	11 8
कर्नाटक	268 2
केरल	274.1
मध्य प्रदेश	1492 7
महाराष्ट्र	630 3
उड़ीसा	646 5
पजाब	197 8
राजस्थान	227 1
तमिलनाडु	466 9
उत्तर प्रदेश	376.2
पश्चिम बगाल	768.3
जम्मू और कश्मीर	5 7
अन्य राज्य और सघ क्षेत्र (दिल्ली को छोड़कर)	67 9
गोआ	3 3
अविभाजित तथा अन्य	1734 9
जोड	11451 2

विवरण- II

राजस्थान के लिए 1977-78 की वार्षिक योजना में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित उद्योग (विशाल और मध्यम तथा खनिज विकास) सम्बन्धी योजनाओ का विवरण ।

क्र०स०	योजना का नाम
I	विशाल और मध्यम उद्योग
	राजस्थान औद्योगिक और खनिज विकास
	राज्य उद्यम विभाग
	तेल चालित वायलरों का कोयला चालित बायलरो मे रूपान्तरण
	आन्तरिक लेखा परीक्षा दल—
	राज्य उद्यम विभाग
	नमक धुलाई कारखाना

1	2
	नमक क्षेत्र का विकास (नया)
	नमक कारखानों का विकास (नया)
	परियोजना रिपोर्ट सेल
	तोल एवं माप
	औद्योगिक क्षेत्र
	परियोजना विरूपण सेल
II.	खनिज विकास
क.	खान और भूविज्ञान विभाग
	गहन खनिज अन्वेषण सर्वेक्षण, खानों और भूविज्ञान विभाग का पुनर्गठन और विस्तार
	ब्रदान सुधार योजना
	लघु खनन पट्टेदारों को ऋण
	खानों एवं खदानों के लिए पहुंच मार्ग
	फास्फेट खनन परिष्करण—झामारकोटरा
ख.	राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड शेयरों की खरीद

Scrutiny of Savings through various Subsidies

3366. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the suggestion made by Dr. Ashok Mitra, West Bengal's Finance and Planning Minister at a press conference on 23rd January, 1978 that savings could also be made in respect of food subsidies (totalling about Rs 475 crores), export subsidies to big industrialists (Rs 150 crores) and that rail freight subsidy and the hidden subsidy through the banking system should also be subjected to a scrutiny; and

(b) if so, the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir. These subsidies are indicated at appropriate places in the Budget Documents of 1978-79, relating to the Railways and the Central Government; there the correct figures relating to these subsidies are also shown.

(b) It is Government's policy to review all subsidies and to reduce them progressively. In doing so, the effects of such economies on commodity prices and the cost of living would be borne in mind. Besides, the rail freight subsidy has also been brought to the notice of Railway Convention Committee, 1973 which examined the social burdens on Indian Railways. The Ninth Report of the Committee contains recommendations in this regard, on which the Government is taking action.

केन्द्रीय सरकार द्वारा राजसहायता

3367. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1977–78 के दौरान समाज के विभिन्न श्रेणियों तथा वर्गों के लोगों को राज-सहायता के रूप में 100 करोड़ रुपये की राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1970–71 से आज तक कुल कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए और समाज की पिछड़ी जातियों को किस प्रकार के लाभ दिये गये ; और

(घ) वर्ष 1978–79 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राजसहायता देने का विचार है ?